उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र

7310. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित विकास केन्द्रों का कार्यकरण, पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के कारण प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में और नए केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश में 8 विकास केन्द्रों को शामिल किया गया है जिनमें से तीन केन्द्रों नामतः बुलन्दशहर, जौनपुर तथा गोरखपुर, में विकास पर 31.12.94 कि स्थिति के अनुसार, राज्य सरकार ने लगभग 20.5 करोड़ रुपये कुल खर्च दर्शाया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अब तक 12.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

बिजली और जल आपूर्ति, संचार इत्यादि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ राज्य सरकारें द्वारा विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। एक विकास केन्द्र को विकसित करने के लिए संसाधन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिन्हें बाजार ऋणों के जरिए जुटाया जाता है। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार का योगदान 10 करोड़ रुपये है।

इन केन्द्रों को शीघ्रता से स्थापित करने में सहायता करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा पूर्व वित्तियन के बारे में जोर दिए बिना अपने योगदान को जारी करने का निर्णय किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी और भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड

7311. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड और भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड की स्थिति दयनीय है;

(ख) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से इन दोनों कंपनियों को पुनर्जीवित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) जी, हां। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड के कार्यनिष्पादन में मुख्यतः रेलवे वैगनों वे कलपुर्जों की कुल खरीद में कमी के कारण ह्रास हुआ है। दोनों कंपनियों औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित कर दी गई हैं। बी आई एफ आर की अंतिम सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Sick units in Gujarat registered with BIFR

7312. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the names of the sick industrial units in Gujarat registered with the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR-) as on 31st January, 1995;

(b) the names of the other States which top in having the maximum sick industrial units; and

(c) what are the further plans for setting these units viable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.